माननीय राज्यपाल महोदय का उद्‌बोधन

विषयः उत्तराखंड में समुदाय और संरक्षण, भविष्य के लिए एक रोड मैप।

(Communities & Conservation in Uttarakhand a Road Map for the Future)

(दिनांक 13 जून, 2024)

जय हिन्द!

देवभूमि उत्तराखंड जिसके मस्तक के रूप में पर्वत राज हिमालय विराजमान है, इसकी स्थलाकृति बहुत विविधतापूर्ण है, बर्फ से ढकी चोटियाँ, ग्लेशियर, गहरी घाटियाँ, गरजती नदियाँ, खूबसूरत झीलें और दक्षिण में मिट्टी से भरे मैदानों के साथ उत्तराखंड की स्थलाकृति अत्यधिक विविध है।

प्रकृति प्रदत अनमोल खजाने से परिपूर्ण उत्तराखंड वनस्पतियों और जीवों की विविधता से समृद्ध है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भौगोलिक और जलवायु विविधता के कारण हिमालय से लेकर तराई के मैदानों तक विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं।

उत्तराखंड, भारत में साइंस बेस्ड वन प्रबंधन में अग्रणी राज्य रहा है। देहरादून को हमे ा से वानिकी का हब माना जाता है और अधिकांश राष्ट्रीय वानिकी संस्थान यहीं स्थित हैं। वैज्ञानिक वन प्रबंधन के कारण ही यहां पर लगभग आधे राज्य के वन क्षेत्र में वृद्धि होती रही है।

भारत की 1988 की वन नीति के परिणामस्वरूप, उत्तराखंड में संरक्षण की पहल को बढ़ावा मिला और संरक्षित क्षेत्र बढ़कर राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के 15 फीसदी तक पहुंच गया, जो राष्ट्रीय औसत से तीन गुना है, जो हमारे लिए गर्व की बात है।

उत्तराखण्ड में कॉर्बेट, फूलों की घाटी और नन्दा देवी जैसे कुछ वि व स्तरीय प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। जैव विविधता संरक्षण के तहत संरक्षित और अन्य वन क्षेत्रों का तेजी से प्रबंधन किए जाने के परिणाम शानदार रहे हैं।

इस वजह से राज्य में पुष्प और जीव–जंतुओं की बेहतरीन संख्या, घनत्व और विविधता है, राज्यों में बाघों की संख्या जो 2006 में 178 थी वो 2022 में बढ़कर 560 हो गई है। राज्य के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में दुनिया में कहीं भी बाघों का घनत्व सबसे अधिक है। पक्षियों की 710 प्रजातियों के साथ, राज्य देश में सबसे अच्छी पक्षी विविधताओं में से एक है।

यह प्र ांसनीय है कि वन विभाग के माध्यम से स्थानीय समुदायों ने भी अपने तरीके से वन्य एवं वन्यजीव संरक्षण में अहम योगदान दिया है। वे विभिन्न तरीकों से होने वाले नुकसान के बावजूद अपने आसपास रहने वाले जंगली जानवरों के प्रति बहुत सहनशील एवं संवेदन ील हैं।

हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में स्थानीय समुदायों का जीवन उनके आसपास के जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों से गहराई से जुड़ा हुआ है। वे परंपरागत रूप से अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए जंगलों पर निर्भर रहे हैं। स्थाई रूप से वे अपने गांवों के आसपास के जंगलों का उपयोग ईंधन, चारे और छोटी लकड़ी के लिए करते रहे हैं।

ग्रामीणों की वनों पर निर्भरता को ध्यान में रखते हुए, केवल उत्तराखंड के लिए वन प्रबंधन प्रणाली ''वन पंचायत'' के रूप में स्थापित की गई जिसके माध्यम से गांवों के करीब के जंगलों को स्थानीय सामुदायिक संस्था ''वन पंचायत'' द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है। प्रदे ा में 11000 से अधिक ऐसे वन पंचायत हैं जिनका प्रबंधन स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता है और उनका उपयोग उनकी बुनियादी जरूरतों के लिए किया जाता है, जो कि एक अच्छी पहल है।

मुझे बताया गया है कि गांवों के नजदीक लगभग 45 फीसदी वन क्षेत्र है गांवों के करीब होने के कारण इसके प्रबंधन में कई समस्याएं और चुनौतियाँ भी हैं। ये समस्याएं राज्य में व्यावहारिक रूप से हर जगह अलग–अलग स्तर पर सामने आ रही हैं और स्थानीय लोगों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। इस समस्या का प्रभावी निदान किया जाना जरूरी है।

राज्य में कई जंगली जानवर खासकर तेंदुए जो लोगों के साथ सीधे मुठभेड़ कर रहे हैं जिसके कारण कई मामलों में जन हानि भी हो रही हैं। कई जानवर फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस कारण से वन्य जीवों के प्रति लोगों का दृश्टिकोण बदला है। वन विभाग को इस तरह के नुकसान को कम करने के पुरजोर प्रयास करने होंगे।

'तेंदुए के साथ रहना' है, यह पहल ऐसी खतरनाक मुठभेड़ों को कम करने के लिए एक अभिनव उपाय प्रतीत होता है और इसमें बहुत सारे वादे हैं। यह अच्छी बात है कि इस कार्यक्रम के तहत वन विभाग इस समस्या से निपटने के लिए स्थानीय समुदायों को बड़े पैमाने पर शामिल कर रहा है।

वन्य जीव संघर्श (Man Animal Conflict)के निवारण हेतु, टिहरी में सफलता के बारे में सुनकर बहुत संतुष्टि हुई जहां इस दृष्टिकोण को प्रायोगिक आधार पर आजमाया गया था। मुझे बताया गया है कि यह दृष्टिकोण अब अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ाया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में हम अपने लोगों को जंगली जानवरों से बेहतर सुरक्षा प्रदान कर सकेंगे।

इस वर्ष जंगल की बढ़ती आग की घटनाएं एक बहुत गंभीर चिंतनीय मुद्दा है, शुष्क मौसम और सर्दियों में कम बारिश के कारण इस वर्श उत्तराखण्ड में वनाग्नि की बहुत घटनाएं हुई हैं।

अक्सर देखा गया है कि जंगलों में आग लगभग हमेशा लोगों द्वारा या तो लापरवाही से या जानबूझकर लगाई जाती है, इसलिए इसका समाधान खोजने के लिए लोगों को शामिल करने की अधिक आवश्यकता है।

इसके अलावा आग गांवों के नजदीक लगती है जहां स्थानीय लोग वन विभाग की टीमों से काफी पहले पहुंच सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए वन विभाग अब लोगों को इस अभियान में अव य ही शामिल करें।

अल्मोड़ा में शीतलाखेत एक अद्भुत और आशाजनक मॉडल बनकर उभरा है। यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि कैसे स्थानीय लोगों ने आग के खतरों को कम करने के लिए जंगलों और गाँव की फसल भूमि का प्रबंधन करना सीख लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने क्षेत्र में वनों का संरक्षण और संवर्धन भी किया है, जो कि सराहनीय है।

हमें उम्मीद है कि भविष्य में राज्य के अन्य क्षेत्रों से भी ऐसे उदाहरण सामने आएंगे। अधिकांश जंगल की आग का कारण चीड़ के पेड़ों से गिरे पिरूल को माना जाता है। इसके संग्रह और उपयोग के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए ताकि आग की संभावना काफी कम हो सके। स्थानीय लोगों को भी इसके उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

बदलते समय में जब स्थानीय लोगों की जंगल पर निर्भरता कम हो रही है, इको टूरिज्म के माध्यम से स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक आजीविका उपलब्ध कराई जाए जिससे जंगलों को विकसित करने और इसके संरक्षण में स्थानीय लोगों की मदद मिल सके।

प्रदेश में वनस्पतियों और जीवों की विविधता, आसान पहुंच, उत्तराखंड के प्रकृति आधारित पर्यटन के विकास के लिए अद्भुत अवसर प्रदान करता है। इसलिए हमें स्थानीय समुदायों की भागीदारी से इको टूरिज्म के विकास के लिए मजबूत पहल करनी होगी। विभाग युवाओं को नेचर गाइड के रूप में प्रशिक्षित करें ताकि वे इसके माध्यम से आजीविका कमा सकें।

यह बहुत अच्छी बात है कि स्थानीय लोगों द्वारा होमस्टे स्थापित किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से पर्यटक राज्य के सुदूर कोनों में पक्षी और तितली विविधता का आनंद ले रहे हैं। कई स्थानीय समुदाय अब स्वयं पक्षी, तितली या प्रकृति उत्सवों का आयोजन कर रहे हैं और दुनिया भर से इको टूरिस्टों को आमंत्रित कर रहे हैं। पर्यटन का यह स्वरूप पर्यावरण के अनुकूल भी है और सुखद भविष्य के लिए एक बेहतर प्रयास भी है।

उत्तराखंड राज्य, देश में एक आदर्श उदाहरण है जहां पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था एक साथ चलती है। रामनगर कॉर्बेट परिदृश्य इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जहां कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बाहर भी बड़ी संख्या में बाघ पनप रहे हैं। बाघ उत्कृष्ट पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत है।

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बाहर कुमाऊं में बाघों की बढ़ती संख्या, 140 से 229 लगभग 1.6 गुना वृद्धि से साबित हो रहा है कि वन विभाग अच्छे तरीके से जंगल का प्रबंधन कर रहा है। इस क्षेत्र में वन्यजीव पर्यटन ने बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा किया है। मुझे प्रसन्नता है कि 2023–24 में युवा नेचर गाइड द्वारा लगभग 4 करोड़, जिप्सी मालिकों द्वारा 14 करोड़, स्थानीय महिला एसएचजी द्वारा 25 लाख रुपए कमाए गए हैं।

आज के इस गहन विचार–विमर्श से स्पश्ट है कि राज्य में वन और वन्यजीव प्रबंधन की गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए समुदायों और वन विभाग को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। वन विभाग ने इस दिशा में एक अच्छी शुरुआत की है। मैं वन विभाग को ऐसे प्रयासों में सफलता की कामना करता हूँ। मुझे वि वास है कि सरकार और समुदायों के एक साथ मिलकर काम करने से, उत्तराखंड के वनों और वन्य जीवन के लिए एक उज्ज्वल भविष्य स्थापित हो सकेगा।

जय हिन्द!